अगस्त 2025

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

अखिलेश की हुंकार

हर बाधा बंदिश पार

R.N.I. No. 68832/97

पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाना ही सच्चा समाजवाद है। इन वर्गों को सशक्त बनाने और समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास रुकने नहीं चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के लिए इन वर्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन
अगस्त 2025
वर्ष 26 | संख्या 10

अंदर

बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है आज़ादी 05

06 कवर स्टोरी

अखिलेश की हुंकार हर बाधा, बंदिश पार

PDA का बढ़ता दायरा 24

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रति बढ़ते विश्वास का नतीजा है कि दूसरे राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2027 में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं।

अखिलेश ने सदन में सरकार की बखिया उधेड़ी 22
स्कूलों के विलय पर भाजपा की पिटी भद 32

PDA काव्य विचार

हम PDA के लोग सभी,
हम साथ चलेंगे मिलकर सभी
हम देश के वासी एक सभी ,
करते सबका सम्मान सभी
ये प्यारा संविधान जिंदाबाद
पूरा PDA जिंदाबाद !

- सत्येश पच्चासी
बख्शी का तालाब विधानसभा, लखनऊ

प्रिय पाठकों,

PDA काव्य विचार के लिए आपकी स्वरचित लघु कविता का स्वागत है। केवल उन्हीं लघु कविताओं पर विचार किया जाएगा जो PDA केन्द्रित, सुस्पष्ट, मौलिक, न्यूनतम 4 से 6 लाइनों में टाइपशुदा होंगी। अपनी लघु कविता ईमेल teamsbeditorial@gmail.com पर अपने नाम और पते के साथ भेजें।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव
☎ 0522 - 2235454
samajwadibulletin19@gmail.com
bulletinsamajwadi@gmail.com
Mob:- 9598909095
/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित
R.N.I. No. 68832/97

त्यौहार

बहनों ने अखिलेश को बांधी PDA राखी

बुलेटिन ब्यूरो

रक्षाबंधन पर्व पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें PDA राखी बांधते हुए 2027 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प लिया। कई बहनों ने सपा मुखिया को सैफई में राखी बाँधी।

श्री जनेश्वर मिश्र जी की बहन, उनके दामाद तथा बेटे ने श्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर राखी बांधी। समाजवादी किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह किन्नर ने श्री अखिलेश यादव को विजय तिलक लगाया और 2027 में मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने बहनों से वायदा किया कि वे माताओं-बहनों के लिए और काम करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के सम्मान एवं जीवन निर्वहन के लिए समाजवादी पेंशन की व्यवस्था करेंगे। समाजवादी सरकार बनने पर उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आज नफरत की राजनीति हो रही है, आपसी रिश्तों में जहर घोला जा रहा है। रक्षाबंधन के पर्व से परस्पर सद्भाव और प्रेम का संदेश जाना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव एवं राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहे।

रक्षाबंधन पर श्री अखिलेश यादव की भावनाओं से अभिभूत बहनों ने भी संकल्प लिया कि वे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं ने संकल्प दोहराया कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है क्योंकि प्रदेश में तभी खुशहाली आएगी और महिलाओं को उनका हक तथा सम्मान मिल सकेगा।

बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है आज़ादी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी ने 15 अगस्त को 79 वें स्वतंत्रता दिवस को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया। समाजवादी पार्टी के जिला व महानगर कार्यालयों पर ध्वजारोहण के बाद मिष्ठान का वितरण हुआ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रध्वज का अभिवादन करते हुए देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से आए कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है। भाजपा ने देश को संकट में फंसा दिया है। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है। वह अपना नॉनवेज दूध जबरन भारत पर थोपना चाहता है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा से बचाना हैं। भाजपा के कारण लोकतंत्र खतरे में है। वोट से लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना हैं। भाजपा को हटाना राष्ट्रहित में है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया है। पीडीए को हमें मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्र-नौजवान, किसान, व्यापारी के साथ आम जनता खुशहाल होगी। संविधान, लोकतंत्र बचेगा। आरक्षण से रोजगार मिलेगा।

इससे पहले श्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रध्वज का अभिवादन करने के बाद कहा कि आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो यह भी याद रखें कि हमारे सामने दुनिया की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा किसान जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

कवर स्टोरी

अखिलेश की हुंकार

हर बाधा बंदिश पार

बुलेटिन ब्यूरो

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के विरोध में INDIA गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अहम भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है।

इसकी ताजा बानगी 11 अगस्त को नई दिल्ली में विपक्षी दलों के 300 सांसदों की ओर से संसद भवन से निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकालने के अभियान में दिखी। विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने लाख जतन किए मगर सरकार की सभी बाधाएं श्री अखिलेश यादव ने फिर तोड़ दीं और अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस की बैरिकेडिंग लांघकर भाजपा को PDA की ताकत का अहसास करा दिया।

दरअसल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को आगे जाने से रोक दिया। एकबारगी लगा कि देश की चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग के साथ निकले मार्च का संदेश उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन संघर्षों के समाजवाद की शानदार परंपरा के झंडाबरदार श्री अखलेश यादव ने पलक झपकते माहौल बदल दिया।

पुलिस के बैरीकेड की परवाह किए बिना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उस पर चढ़ गए और उस ओर फांद गए जिधर जाने से विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाया था। श्री अखिलेश यादव की छलांग देखते ही विपक्ष के अभियान में नई जान आ गई।

बैरिकेडिंग हटवाने के लिए श्री अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्षी सांसदों के लगातार बढ़ते विरोध से सरकार घबरा गई और उसे लगा कि श्री अखिलेश यादव कहीं निर्वाचन सदन न पहुंच जाए इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव, आजमगढ़ के सांसद धर्मेन्द्र यादव आदि सांसदों को भी गिरफ्तार कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ले जाया गया। शाम को उनकी रिहाई हो सकी। इससे पहले श्रीमती डिंपल यादव समेत अन्य सांसदों ने पुलिस के रोके जाने पर सड़क पर धरना भी दिया।

श्री अखिलेश यादव जुल्म-ज्यादती के खिलाफ हमेशा ही मुखर रहे हैं। उनके सामने भाजपा सरकार की बंदिशें, बाधाएं कभी भी रुकावट नहीं बन सकीं और वह हमेशा ही पीडीए के हितों की आवाज उठाते रहे हैं। न कभी डरे न कभी झुके। मजबूत इरादों, लड़ने और हमेशा ही संघर्ष की हुंकार भरने के कारण ही वह पीडीए समाज का नेतृत्व कर रहे हैं।

उनके संघर्षों की वजह से ही पीडीए समाज ने लोकसभा चुनाव में उनका भरपूर समर्थन कर यूपी से भाजपा का सफाया कर सपा को 37 सीटें जिताकर देश की राजनीति का सिरमौर बना रखा है। यह पीडीए की एकता की ही ताकत है कि आज समाजवादी पार्टी संसद में देश की तीसरी बड़ी पार्टी है।

जिसका नतीजा यह है कि श्री अखिलेश यादव और जोरदार तरीके से पीडीए के मसलों को उठा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि बीते दिनों श्री अखिलेश यादव की जातीय जनगणना की मांग को पूरे देश में बल मिला और बिहार में इसे करवाया गया। श्री अखिलेश यादव का स्पष्ट कहना है और वह इसपर कायम हैं कि जातीय जनगणना से पिछड़े, दलित, वंचित और शोषितों की संख्या का पता चलेगा और उसी अनुरूप उन्हें अधिकार व सम्मान मिलेगा।

यही वजह है कि पीडीए समाज 2027 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर श्री अखिलेश यादव को सत्ता सौंपने के लिए तैयार बैठा है ताकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को और धार दी जा सके।

यह पहली बार नहीं हुआ जब भाजपा के इशारे पर श्री अखिलेश यादव की आवाज दबाने की पुलिस ने कोशिश की थी। इससे

पहले भी लखनऊ में भाजपा ऐसी हिमाकत कर चुकी है और उसे तब भी मुंह की खानी पड़ी थी। पुलिस ने कई मौकों पर लखनऊ में बैरिकेडिंग कर श्री अखिलेश यादव को रोका था मगर उन्होंने यह बाधाएं तोड़ दी थीं। जेपीएनआईसी में जब श्री अखिलेश यादव को रोका गया था तो वह गेट फांद गए थे।

11 अगस्त को दिल्ली ने भी श्री अखिलेश यादव का वही जज़्बा देखा। जब जुल्म-सितम के खिलाफ देश की राजनीति में सबसे मुखर आवाज बन चुके श्री यादव ने भाजपा को पीडीए की ताकत दिखाते हुए बैरिकेडिंग को लांघकर संघर्ष की हुंकार भर दी।

श्री अखिलेश यादव के इस साहसिक कदम ने पीडीए को ताकत तो दी ही, स्पष्ट संदेश दे दिया कि श्री यादव के रहते उनकी आवाज न दबाई जा सकती, न झुकाई जा सकती। उनके अगुआ श्री अखिलेश यादव हर जुल्म सितम के खिलाफ उनके साथ हैं चाहे भाजपा सरकारें कितनी भी बाधाएं, बंदिशें लगा ले।

बिहार में हो रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ डटकर खड़े श्री अखिलेश यादव के इस सवाल का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीते चुनावों एवं कुछ उपचुनावों में हुई धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए 18 हजार शपथ पत्र के मामले में क्या कार्रवाई हुई?

21 जुलाई से जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तभी से INDIA गठबंधन एकजुट होकर बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और 11 अगस्त को संसद भवन से निर्वाचन सदन

डाइनामाइट
न्यूज़
MKN
NEWS

तक निकलने वाले मार्च से पहले भी लगातार संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, सभी समाजवादी सांसद प्रमुखता से शामिल हो रहे हैं ताकि पीडीए समाज के खिलाफ उठने वाले हर कदम को रोका जा सके।

श्री अखिलेश यादव ने भाजपा के इशारे में लगाई गई पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघकर पीडीए के अधिकारों के लिए संघर्ष का शंखनाद कर दिया है। साथ ही यह भी संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए अब पीडीए समाज को मजबूती के साथ संघर्ष करना होगा क्योंकि बिना संघर्ष के भाजपा जाने वाली नहीं है और चुनावों में उसकी धांधली कायम रहेगी। यह सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा ही पिछड़ों, दलितों के आरक्षण के खिलाफ रही है और वह इसके लिए निजीकरण का रास्ता तलाश रही है। हाल ही में यूपी में उसने स्कूलों का मर्जर या पेयरिंग का आदेश इसीलिए दिया था ताकि पिछड़ों, दलितों को शिक्षा से दूर कर दिया जाए। भाजपा जानती है कि शिक्षित होने के बाद यह तबका अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो जाएगा तो उसके लिए परेशानी होगी लेकिन अब पीडीए समाज भाजपा के झांसें में नहीं आएगा और भाजपा को हटाकर दम लेगा। 2024 में उसने ऐसा करके दिखाया है और 2027 का इंतजार कर रहा है ताकि यूपी से भाजपा की विदाई की जा सके। 11 अगस्त को श्री अखिलेश यादव के दिखाए गए दम ने पीडीए को और दमदार कर दिया है। तय हो गया है कि अब भाजपा जाएगी, खुशहाली आएगी।

SIR पर विपक्ष के तेवरों का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे अखिलेश

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर INDIA गठबंधन को मजबूती दी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के खिलाफ जब INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया तो श्री अखिलेश यादव ने उसमें अपनी भरपूर सहभागिता देते हुए संदेश दे दिया कि गठबंधन धर्म निभाने में उनका कोई सानी नहीं है।

यही वजह रही कि इस विरोध प्रदर्शन का श्री अखिलेश यादव प्रमुख चेहरा बनकर उभरे और देश ने यह देखा कि भाजपा के खिलाफ और पीडीए की लड़ाई लड़ने का माद्दा सिर्फ श्री अखिलेश यादव में ही है।

यह पहली बार नहीं है जब श्री अखिलेश यादव ने INDIA गठबंधन को मजबूती दी हो। लोकसभा चुनाव से पहले बने INDIA गठबंधन को श्री अखिलेश यादव ने हर स्तर पर मजबूत किया और लोकसभा चुनाव में यूपी में इस गठबंधन की अगुआई की।

श्री अखिलेश यादव की अगुआई का ही नतीजा था कि पीडीए के बूते उन्होंने भाजपा को यूपी में बुरी तरह पस्त करते हुए समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जितवाकर INDIA गठबंधन को मजबूती दी। श्री यादव ने कांग्रेस को भी 6 सीटें जितवाकर साबित कर दिया कि भाजपा को हराने की कूवत समाजवादियों में ही है।

INDIA गठबंधन को मजबूत करने की जब भी जरूरत पड़ी है, श्री अखिलेश यादव ने न सिर्फ उसका साथ दिया है बल्कि हर संभव तरीके से भाजपा और उसके सहयोगी दलों का मुकाबला भी किया है। यूपी की भाजपा सरकार को जनहित के तमाम मुद्दों पर लगातार घेरते रहने की वजह से भाजपा

परेशान है और श्री यादव का राजनीतिक कद देश में लगातार बढ़ रहा है।

श्री यादव की मेहनत का नतीजा है कि देश में पीडीए समाज एकजुट हो रहा है। पीडीए समाज की एकजुटता से यूपी में बदलाव का पूरा माहौल बन चुका है और मंत्रियों में ऐसी घबराहट फैल चुकी है कि वे अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रस्सासकशी अब किसी से छिपी नहीं है।

श्री अखिलेश यादव जिस तरह स्पष्ट विजन, सकारात्मक सोच, जनहित की आवाज बनकर राष्ट्रीय राजनीति में उभरे हैं, वह दिन दूर नहीं जब उनके नेतृत्व में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और उसे वैसे ही मुंह की खानी होगी जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे शिकस्त मिली थी।

चुनाव आयोग की साख पर दाग

यूपी के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं इस पर बहस होनी चाहिए। अभी उस पर वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई देना स्वयं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एवं चुनावी पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। जनता का विश्वास किसी संवैधानिक संस्था से डिगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होगे। ऐसा लगता है कि भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को 18 हजार वोट कटने पर शपथ पत्र दिया था। उपचुनाव में जो वोटों की लूट हुई उसकी जानकारी दी थी। चुनाव आयोग दिए गए शपथ पत्रों का जवाब दे। चुनाव आयोग बताए कि क्या कार्यवाही हुई। गड़बड़ी में शामिल तमाम जिला अधिकारियों को निलंबित किया जाए।

श्री यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठ चुकी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी सरकार ने मिलकर अधिकारियों के सहारे वोट की लूट की थी। कुंदरकी, फैजाबाद, मीरापुर के विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान खुले आम धांधली की गई थी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा एसआईआर का विरोध संविधान को ही बचाने की कोशिश है। ये हारती हुई भाजपा की निशानी है। जनता भाजपा के खिलाफ वोट न डाल सके इसलिए भाजपा जनता से वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है। भाजपा चुनाव में लगे अपने चुनिंदा अधिकारियों को बाकायदा टारगेट देती है कि कितने फर्जी वोट डालना है। एक वीडियो में एक आदमी छह-छह वोट डालने का दावा कर रहा था।

भाजपा समर्थक एक पुलिस अधिकारियों का वीडियो भी आया था, जिसमे पिस्तौल तान कर महिला मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा था। उत्तर प्रदेश में कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनावों में भाजपा के वोट हथियाने के तौर तरीकों की बानगी साफ दिखाई दी थी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह आशंका अब सच लगती है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने खिलाफ डाले गये वोट खारिज करवा के और डीएम के दबाव से जीत के सर्टिफिकेट बदला कर दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर खुद को जिताने का काम किया था।

उन्होंने कहा कि एक बात तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि चुनाव आयोग की साख बहुत हद तक जनता की निगाहों मे गिर गई है। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। अब समाजवादी पार्टी इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। सन् 2027 के चुनावों में भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ से वोटों की हेराफेरी और जबरन चोरी कतई नही होने पाएगी।

दबे पांव आता साइलेंट आपातकाल

राजकुमार भाटी

बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अर्थात S I R प्रक्रिया की आलोचना में 1 अगस्त के 'दि हिंदू' में छपे एक लेख में अधिवक्ता और प्रसिद्ध समाजसेवी संजय हेगड़े लिखते हैं- "आपातकाल के लिए हमेशा सड़कों पर टैंक उतारने की जरूरत नहीं होती। एक चुपचाप आपातकाल भी होता है जैसा देश में इस समय मौजूद है। यह तब आता है जब नाम गायब होते हैं, अवधियां पूरी नहीं होतीं और सवालों के जवाब नहीं मिलते। यह तब आता है जब राज्य तंत्र नागरिकता को अधिकार नहीं बल्कि अहसान समझता है। हमें यह सिद्धांत फिर से स्थापित करना होगा कि मत देने का अधिकार कागजात का नहीं, जनता का है। सड़क, समाज और सुप्रीम कोर्ट को जोर से कहना चाहिए कि भारत माता सभी संतानों की माता है। और जब कोई उसकी

शरण चाहता है तो वह धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करती।"

बिहार में चला मतदाता सूचियों का कथित विशेष गहन पुनरीक्षण देश में अघोषित आपातकाल का अहसास कराता है। जब विधान सभा चुनाव सिर पर पर हैं, चुनाव आयोग पर अचानक मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की सनक सवार हो गई।

24 जून को एक आदेश पारित करके बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं से कहा गया कि वे 25 जुलाई तक आयोग द्वारा जारी प्रपत्र को भरकर अपनी फोटो और पहचान पत्र के साथ जमा करें।

बिहार जहां की बड़ी आबादी रोजी-रोटी की तलाश में राज्य से बाहर रहती है और जुलाई-अगस्त के महीनों में जिस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है, वहां के लगभग आठ करोड़ मतदाताओं को फार्म भरने, जमा करने और पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए मात्र एक महीने का समय दिया गया और कहा गया कि जो मतदाता 25 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। 1 अगस्त को जब पुनरीक्षित मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें पुरानी मतदाता सूची के 66 लाख नाम गायब थे।

चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में कई झोल हैं। 24 जून को आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि बिहार में जो कोई 2003 से पहले मतदाता हैं वह भारत का नागरिक माना जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बने सभी लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश ने बिहार के दो करोड़ उन मतदाताओं की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह

लगा दिया जो कि 2003 के बाद मतदाता बने हैं।

क्या चुनाव आयोग के पास किसी की नागरिकता छीनने अथवा किसी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता पंजीकरण अधिकारी (1995) और मो रहीम अली बनाम आसाम राज्य (2024) के मुकदमों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के बिना मताधिकार छीनना असंवैधानिक है। नागरिकता को मनमाने ढंग से न तो छीना जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है।

लेकिन चुनाव आयोग समूचे विपक्ष, जनता, मीडिया और न्यायालय की आवाज को दरकिनार कर बिहार में मनमाने तरीके से मताधिकार को छीनने और नागरिकता को नकारने के प्रयासों में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में दायर की गई विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे और कई सुझाव दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को पहचान पत्र के प्रमाण के तौर पर मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग का जवाब था कि इनमें

फर्जीवाड़ा हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जीवाड़ा तो किसी भी प्रपत्र में हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता को कागज प्रस्तुत करने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए गए तो वह हस्तक्षेप करेगा। प्रश्न यह नहीं है कि अधिक नाम कटे या कम नाम कटे। सवाल यह है कि यदि एक भी वैध नागरिक का मताधिकार और नागरिकता खतरे में पड़ती है तो यह संवैधानिक व्यवस्था की विफलता होगी।

पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में खानापूरी, लीपापोती और फर्जीवाड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में इस तरह के समाचार आए हैं कि प्रक्रिया में लगे कर्मचारी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने सबूतों के साथ कई प्रकरण उजागर किए हैं और बताया है कि भारी संख्या में कर्मचारियों ने खुद फार्म भरके पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। बहुत से ऐसे लोगों के फार्म भी अपलोड कर दिए गए हैं जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है।

जिला पटना के मसौढ़ी ब्लाक में एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया गया। प्रमाण पत्र में बाकायदा कुत्ते का फोटो लगा है। आवेदक का नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया देवी लिखा है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण की गहनता का मात्र एक उदाहरण है।

यह सब जानने-समझने के बाद सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस सारी कवायद के पीछे सरकार अथवा चुनाव आयोग का असली मकसद क्या है? असल में यह भारतीय जनता पार्टी की जानी पहचानी उस तिकड़म का एक हिस्सा है जिससे वह चुनावों में धांधली कर सत्ता में बने रहना चाहती है।

शुभ संकेत यह है कि श्री अखिलेश यादव इन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में चल रहे हैं और भाजपा की तमाम साजिशों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। साफ है कि बदलाव आएगा, भाजपा जाएगी और सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा

जातीयता और साम्प्रदायिकता का मायाजाल कमजोर होने के बाद मतदाता सूचियों और मतदान को प्रभावित करके सत्ता हासिल करने की व्यूह रचना की जा रही है। इस व्यूह रचना के तहत ही महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं, बिहार में 66 लाख वोट काट दिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में PDA के मतदाताओं को पुलिस लगाकर वोट डालने से रोक दिया जाता है। तभी संजय हेगड़े को लिखना पड़ता है कि यह बिना टैंकों के दबे पांव आ रहा साइलेंट आपातकाल है।

देश की जनता को इसे समझने की जरूरत है कि भाजपा किस तरह येन-केन-प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए व्यूह रचना कर रही है। यह भी समझना होगा कि भाजपा जानती है कि वह जनहित के तमाम मुद्दों पर विफल हो चुकी है और त्राहिमाम् कर रही जनता उसे हटाने पर आमादा है इसलिए वह साजिशों का तानाबाना बुन रही है खासतौर पर PDA उसके निशाने पर है।

आरक्षण छीनने और शिक्षा से PDA को वंचित करने का षड़यंत्र अब नहीं चलने वाला है क्योंकि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए समाज ने देश का माहौल बदल दिया है और पीडीए पूरी तरह जागरुक हो चुका है। देश के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि साइलेंट आपातकाल के खिलाफ पीडीए समाज नई क्रांति की इबारत गढ़ रहा है और आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए उसे श्री अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं।

शुभ संकेत यह है कि श्री अखिलेश यादव इन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में चल रहे हैं और भाजपा की तमाम साजिशों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। साफ है कि बदलाव आएगा, भाजपा जाएगी और सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा। बस, पीडीए समाज को वैसे ही एकजुट रहने की जरूरत है जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में एकजुट होकर पूरे देश को संदेश दिया था।

(लेखक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं)

लोकतंत्र पर खुला डाका है
गहन मतदाता सर्वेक्षण

अरविन्द मोहन
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

पहली अगस्त को बिहार के गहन मतदाता सर्वेक्षण की ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक करने के अगले दिन ही चुनाव आयोग का रिलीज यह विस्तार से बताता है कि बिहार के किसी जिले, किसी दल और किसी व्यक्ति की तरफ ने नाम काटने की एक भी शिकायत नहीं मिली है।

आयोग से भी ज्यादा भाजपा और सोशल मीडिया पर मोदी भक्त इस सूची को प्रचारित प्रसारित करने में जुट गए। अब चुनाव आयोग इसे 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने की अपनी करतूत पर क्लीन चिट बताए तब भी एक बात समझ आती है लेकिन भाजपा के लोग और मोदी भक्त इस सूचना से इतना क्यों उछलने लगे यह समझना थोड़ा मुश्किल है।

असल में यह चुनाव आयोग और उसके बिहार संबंधी इस काम को लेकर पैदा अपराधबोध ही है जो इस तरह कई सफाई

दिला रहा है। आयोग जितना तत्पर विपक्षी हमलों और आरोपों को काटने के मोर्चे पर सक्रिय रहा है उतना सर्वेक्षण में रहता तो इतनी बड़ी संख्या में नाम काटने की जरूरत ही नहीं होती। नाम काटने वाले एक भी व्यक्ति को आयोग ने सूचना दी हो या चेतावनी दी हो इसका प्रमाण नहीं है।

बिना सफाई, गवाही या खुद उपस्थित होकर अपने वजूद को साबित करने का मौका दिए बिना आठ फीसदी से ज्यादा मतदाताओं को उनके वोटिंग राइट से किस तरह वंचित किया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। जिस राज्य के करोड़ों लोग दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हों उन सबसे एक छोटे समय में सारे प्रमाणपत्र पेश करने की उम्मीद कौन कर सकता है।

जिस आयोग ने साल भर पहले ही जिस सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव कराया है और जिससे बनी सरकार शासन चला रही है वह अपनी उसी मतदाता सूची में इतनी ज्यादा गलतियां ढूंढ लेता है यह भी हैरानी की बात है। अगर साल भर में 22 लाख मतदाताओं की मौत का आंकड़ा मान भी लिया जाए तो जगह बदलने या अनुपस्थित पाए जाने वालों को मौका न देने की सफाई तो आयोग को देनी ही चाहिए। फिर आयोग आधार कार्ड और राशन कार्ड को किस आधार पर गहन पुनरीक्षण के काम में मतदाता की पहचान का प्रमाण नहीं मानता इसकी सफाई अभी न सुप्रीम कोर्ट में दी गई है न संसद में।

संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है लेकिन सरकार बहस से भाग रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 26 जनहित याचिकाओं के जवाब में आयोग और सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वह अदालत को मंजूर नहीं है। यह अलग बात है कि हर सुनवाई पर अदालत द्वारा उठाए सवालों को दरकिनार करके भाजपा और मीडिया यही कहता रहा है कि अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। यह बात ऐसे कही जाती है जैसे अदालत ने आयोग को क्लीन चिट दे दी है।

तथ्य यह है कि अदालत ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और पिछले मतदाता पहचानपत्र को वैलिड दस्तावेज मानने का सुझाव देने के साथ चुनाव आयोग द्वारा दिखाई जा रही अनावश्यक तेजी को लेकर टिप्पणियां की हैं।

यह सही है कि हमारा चुनाव आयोग दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन उसके हाथ में 'सत्ता' सिर्फ चुनाव के समय ही रहती है बाकी दिनों उसकी बागडोर भी सरकार के हाथ में ही होती है। आयोग बिहार में जो कर रहा है इसके बाद बंगाल में यही सब दोहराया जाएगा। यही दो राज्य ऐसे हैं जो अभी तक भाजपा के हाथ नहीं आए हैं। मोदी-शाह की जोड़ी इन राज्यों को हथियाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। जो ड्राफ्ट आया है

या जिस तरह से पहचान के मुश्किल दस्तावेज मांगे गए हैं उनसे साफ है कि निशाने पर कौन है।

यह मंशा भांपकर अल्पसंख्यक समाज के लोग औरों से ज्यादा तत्पर होकर कागजात जमा कराते रहे हैं पर नाम काटने संबंधी सूची को देखकर कोई भी कह सकता है कि निशाने पर वही थे और अभी भी उनके नाम अनुपात में ज्यादा कटे हैं, पर विपक्षी इंडिया गठनधान का एकजुट होना यह बताता है कि चीजें भाजपा के लिए आसान नहीं हैं।

पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 26 याचिकाएं दाखिल हैं। अदालत का रुख सख्त बना हुआ है। उसने सुनवाई में सरकारी वकील से कई बातों का स्पष्टीकरण मांगने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनाने में आधार कार्ड, पुराने मतदाता पहचानपत्र और राशन कार्ड को भी विचार के लिए शामिल करने का सुझाव दिया जिन्हे चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया था। इसे ही लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है।

बात घूम फिर कर मतदाता बनाम नागरिकता की बहस और बांग्लादेशी-रोहिंगिया घुसपैठ, हिन्दू-मुसलमान और इससे देश को खतरे पर आ गई है। यह बात ऐसे कही जा रही है जैसे एक बार किसी का फर्जी मतदाता पहचानपत्र बन गया तो उसे पकड़ना और सजा देना संभव ही नहीं है।

अगर आधार, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड की गलती पकड़ी जा सकती है अन्य योजनाओं के फर्जी लाभार्थी पकड़े जा सकते हैं तो मतदाता सूची की गड़बड़ी क्यों नहीं रोकी जा सकती। और यह सब किसका जिम्मा है। अगर लोकसभा चुनाव में इतने बोगस मतदाताओं ने वोट दिया तो दोष किसका है।

भाजपा मानकर चलती है कि उसे मुसलमानों का वोट लगभग नहीं मिलता। विपक्ष अर्थात कांग्रेस और आरजेडी मुसलमान वोट को अपना आधार मानते हैं। उनका इसके लिए चिंतित होना एक तात्कालिक जरूरत है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाला विपक्ष इस बार शुरू से बहुत चौकस रहा है-शोर मचाने से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना

और अदालत का दरवाजा खटखटाने तक। इसलिए यह मसला जल्दी चर्चा में आया। बंगाल भी इस सर्वेक्षण के सवाल पर अभी से गरमाने लगा है। गांव-गांव में खलबली मची है क्योंकि जन्म और निवास प्रमाणपत्र हासिल करना आसान नहीं है और जब करोड़ों लोग बाहर काम करने निकले हों तो यह काम और मुश्किल हो जाता है।

दूसरी ओर चुनाव आयोग और सरकार जल्दी जल्दी यह काम निपटाने और कितनी जल्दी अस्सी या नब्बे फीसदी मतदाताओं का फार्म आ गया यह बताने का अभियान चला रहे थे। इससे विपक्षी अभियान तो मद्धिम नहीं पड़ा है लेकिन लोजपा और जदयू जैसे सहयोगी दल उलझन में हैं और अब खुद भाजपा नुकसान को लेकर डरने लगी है। तेलगुदेशम पार्टी ने भी खुली आलोचना की तो जदयू सांसद गिरधारी यादव अपने अनुभव से पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते दिखे। साफ लगता है कि आयोग की तैयारी आधी-अधूरी है और उसने बहुत काम समय में यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

बात सिर्फ विपक्ष के आरोप या दिए जाने वाले आंकड़ों भर की नहीं है। खुद आयोग के आंकड़े भी इस अभियान की मंशा और प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सामान्य ढंग यही रहा है कि हर साल डेढ़ से दो करोड़ नए मतदाता नई सूची में आ जाते हैं लेकिन 2023 से मतदाता सूची का आकार 18 लाख घट गया है। जाहिर तौर पर इतने ज्यादा नाम काटने की कोई वजह, या उनको दिए गए नोटिस या सुनवाई की खबर भी नहीं आई है। लिहाजा विपक्ष को आशंका है कि नाम अपनी तरफ से काट दिए गए और कोई वैधानिक औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई।

बिहार में कम तैयारी के साथ अगर 'गहन पुनरीक्षण' किया जाता रहा तो यह सचमुच की शुद्ध सूची बनाने के घोषित उद्देश्य के खिलाफ ही जाएगा। । असम में हम ऐसा उलझाव देख रहे हैं जो वर्षों से वैसे ही पड़ा है और हर चुनाव में इस्तेमाल होता है। अब अगर बिहार और फिर बंगाल में ऐसा हुआ तो देश का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद एक जाल में फंसेगा जो हर किसी की नागरिकता को संदिग्ध बना देगा। और जैसा भाजपा के प्रभारी पदाधिकारी को भी लग रहा है कि यह सवाल उसे लाभ देने की जगह घाटा दे सकता है तो मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चुनाव एजेंसी बनकर भी आयोग अगर इस तरह के फैसले करेगा, ऐसे काम करेगा तो उसकी मर्यादा और शक्ति दोनों का ह्रास होगा ही।

अखिलेश ने सदन में सरकार की बखिया उधेड़ी

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बहादुर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की जबकि सीजफायर (संघर्ष विराम) करने पर भाजपा सरकार की बखिया उधेड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार किस दबाव में सरकार को सीजफायर करना पड़ा।

29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री अखिलेश यादव ने देश की सेना का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की साहसी फौजों में जब गिनती होती है तो उसमें भारतीय सेना सबसे आगे दिखाई देती है। सेना के अदम्य शौर्य पर हम सब को गर्व है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैम्पों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त किया।

उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने आतंकी कैम्पों को नष्ट करने के साथ पाकिस्तानी एयर बेस को भी निशाना बनाया। उन्हें भी ध्वस्त किया। जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए पाठ पढ़ा सकती थी और वह फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता ऐसे समय में भारत सरकार पीछे क्यों हट गई ? क्या कारण था कि सरकार को सीजफायर का ऐलान करना पड़ा। सरकार को बताना चाहिए आखिरकार उसे किस दबाव में सीजफायर स्वीकार करना पड़ा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार खुद सीजफायर करेगी लेकिन इनकी मित्रता बहुत लोगों से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपने मित्र से कह दिया कि वही सीजरफायर का ऐलान कर दें।

श्री यादव ने कहा कि आजादी के इतने सालों के बाद आज जिस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है, यह होना ही नहीं चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल बाद भी ये मुद्दे बने हुए हैं। यह बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। यह देश की सुरक्षा और जनता की रक्षा की बात है। उन्होंने सुझाव दिया कि सब लोग मिलकर कोई ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाते जिससे सीमाएं हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत रहें।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। पहलगाम हमले के समय वहां मौजूद पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच उनकी रक्षा करने वाला कोई क्यों नहीं था। सरकार तो दावा करती थी कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी घटना नहीं होगी। वहां पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटक सरकार के भरोसे और आश्वासन पर गए थे।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई। इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? यह घटना इंटेलिजेंस फेल्योर थी। सरकार को बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना न हो उसके लिए क्या-क्या कदम उठा रही है? क्योंकि पहलगाम से पहले पुलवामा की घटना हुई थी, तब भी इंटेलीजेंस फेल्योर की बात सामने आई थी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में शामिल लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं। उसके जरिए जनता से भावनात्मक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेल्योर पर जवाब आना चाहिए। इसके साथ सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तब देश का क्षेत्रफल कितना था और आज देश का क्षेत्रफल क्या है? लोगों को क्षेत्रफल पता होना चहिए।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना के दूसरे दिन जिस तरह का कार्टून भाजपा के आफिसियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति पर हटाया गया, उससे साबित होता है कि भाजपा के लोगों ने दुःख की घड़ी में देश की भावनाओं के साथ शर्मनाक काम किया। भाजपा बताए कि ऐसे असंवेदनशील लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की?

श्री यादव ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि यह इंटेलिजेंस फेल्योर है लेकिन यह नहीं बताया कि फेल्योर क्यों हुआ है। सरकार इस पर जवाब दे। श्री यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया प्रचार निन्दनीय है। ऑपरेशन सिंदूर होना सरकार की विफलता का प्रतीक है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। आपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर दुनिया के किसी देश ने साथ नहीं दिया। यह विदेश नीति का संकटकाल है। पड़ोसी देश अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे देश के साथ नहीं खड़े हुए।

उन्होंने कहा समाजवादियों ने हमेशा सरकार को सीमा को लेकर चेताया है। सरकार को इस पर साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सरकार को इस पर समझौता नहीं करना चाहिए। भाजपा सरकार में सरहदों के साथ देश के व्यापार में भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर समाधान करना चाहिए।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में जितना खतरा आतंकवाद से है उतना ही खतरा चीन से है लेकिन सरकार के फैसले और नीतियां ऐसी हैं कि जो सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है उसी के साथ व्यापार में मदद करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश का व्यापार और कारोबार मजबूत होगा तो कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एसआईआर कराना चाहिए। हर बार चूक हुई, कह कर सरकार अब नहीं बच सकती है। श्री यादव ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का खतरा रहता है लेकिन जो दूसरे देशों से सीमाएं हैं वहां भी खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन सीमा पर स्थिति पहले की गलवान सीमा जैसी नहीं लौटी है। नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्र में गश्ती के लिए बफर जोन उपलब्ध नहीं है। लद्दाख में सैनिकों की भारी तैनाती है। हमारी मांग है कि सरकार अपनी अग्निवीर योजना वापस ले जिससे सेना की कमी पूरी हो सके।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को आतंकवाद और पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए 10-15 साल की योजना बनानी चाहिए। चीन से व्यापार कम करना होगा। अगर चीन से इसी तरह से व्यापार होता रहेगा तो हमारा देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ऐसा लगता है कि चीन से व्यापार कुछ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सभी लोग आतंकवाद के खात्मे और आतंकवादियों के मारने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, देश के सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया। पहलगाम की घटना में किसी दल ने भाजपा के साथ राजनीति नहीं की लेकिन भाजपा और सरकार ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के साथ राजनीति करने की कोशिश की। अगर सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजना था तो राजनीतिक दल तय करते, सरकार नहीं कर सकती थी। आखिरकार यह राजनीति कौन कर रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते, सीमा पर शांति रहे लेकिन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते लेकिन सरकार को समझना होगा कि जो लड़ाई हुई है वह पाकिस्तान से नहीं हुई है। यह लड़ाई चीन से लड़नी पड़ी थी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें गर्व है कि समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है, जब जरूरत होगी तो सेना के फाइटर प्लेन वहां उतर जाएंगे।

PDA का बढ़ता दायरा

बुलेटिन ब्यूरो

फाइल फोटो

समाज का शोषित, वंचित तबका जिस तेजी के साथ PDA को मजबूत करने में जुटा है, उससे साफ है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रति बढ़ते विश्वास का नतीजा है कि दूसरे राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2027 में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं।

PDA की एकजुटता कोई एक दिन में नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने PDA को एकजुट करने के लिए जागरुकता अभियान चला रखा है, उनके अधिकारों की आवाज उठाई और यह बताने में कामयाब हो गए हैं कि एकजुटता से ही पीडीए को उनका हक मिलेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई को धार देने में जुटे श्री अखिलेश यादव जातीय जनगणना कराने के लिए कमर कसे हुए हैं ताकि आबादी के हिसाब से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे तबके को अधिकार और सुविधाएं मिल सकें और PDA का जीवनस्तर भी खुशहाल हो।

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में PDA ने अपनी ताकत और एकजुटता दिखाई थी और भाजपा का सफाया कर दिया था।

पीडीए के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को डोम-मुसहर-नट-धरिकार-बासफोर गरीब समाज के नेता श्री अवधेश बागी मुर्दहवा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नाम एक ज्ञापन राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को सौंपते हुए बताया कि उनके समाज ने 2027 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। ज्ञापन के जरिये डोम-मुसहर-नट-धरिकार-बासफोर गरीब समाज पार्टी ने डोम, मुसहर, नट, धरिकार, बांसफोर, पत्थरकट, थारू जाति की तमाम परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें भाजपा सरकार में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने आश्वस्त किया कि श्री अखिलेश यादव इन मांगो और आवाज के प्रति गंभीर हैं और 2027 में सरकार बनने पर उनके अधिकार उन्हें दिलाए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प लेने वाले डोम-मुसहर-नट-धरिकार-बासफोर गरीब समाज पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल में सर्वश्री प्रमोद भास्कर प्रदेश अध्यक्ष, बबलू बांसफोर प्रदेश उपाध्यक्ष, झकडी बांसफोर प्रदेश सचिव, लालजी बांसफोर प्रदेश कोषाध्यक्ष, बिरेन्द्र कुमार प्रदेश प्रचार प्रभारी, नखडू बांसफोर प्रदेश संगठन प्रभारी, मनोज कुमार प्रदेश प्रभारी, किताबू प्रदेश संगठन मंत्री, पारस बांसफोर मण्डल अध्यक्ष मऊ, बीकेश कुमार

मण्डल अध्यक्ष गाजीपुर, जयमंगल जिलाध्यक्ष गाजीपुर, अनील कुमार जिलाध्यक्ष मऊ शामिल रहे।

28 जुलाई को ही पीडीए को तब और मजबूती मिली जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के समक्ष बुन्देल खंड क्रांति मोर्चा एवं भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कई पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख कार्यकर्ता भी श्री अखिलेश यादव की पीडीए को मजबूत करने की मुहिम में साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी में तेजी से शामिल हो रहे हैं। 4 अगस्त को बसपा के तमाम नेता, प्रमुख कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 2027 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बूथ स्तर तक काम करने का संकल्प लिया। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में सर्वश्री फैजान अहमद सभासद, मोहम्मद हमजा पूर्व प्रधान, फिरोज अहमद, फरहान अहमद, शोएब अहमद, एडवोकेट मोहम्मद अहमद, जावेद अहमद, मेराज अहमद, डॉ. मोहम्मद अली, नौशाद मलिक, अब्दुल हमीद शामिल हैं। 9 जुलाई को आवाज-ए-हिंद के दर्जनों पदाधिकारियों एवं रौनियार समाज देवरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी की सदस्यता ग्रहण की।

जिस तेजी के साथ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ रहा है और पीडीए का दायरा बढ़ा है, वह स्पष्ट संकेत है कि श्री यादव ने पीडीए समाज को एकसूत्र में पिरो दिया है। अब यही पीडीए समाज भाजपा को सत्ता से बेदखल कर 2027 में अपनी सरकार बनाने जा रहा है ताकि पीडीए समाज को उनका अधिकार मिल सके, अन्याय, अत्याचार से छुटकारा मिले।

सीतापुर में PDA की जीत,सपा का परचम लहराया

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में सभी मोर्चे पर फेल भाजपा सरकार को सीतापुर की जनता ने नकारते हुए महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाया है। यह जीत प्रदेश में PDA के लगातार बढ़ते दायरे की एक और बानगी है।

इस सीट पर पीडीए उम्मीदवार की जीत और भाजपा की करारी हार ने पीडीए की एकजुटता को एक बार फिर दर्शा दिया है। यहां की जनता ने भाजपा को पांचवें स्थान पर धकेल कर पूरे प्रदेश को बता दिया है कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है।

यहां हुए उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमिर अराफात को चुनकर संदेश दे दिया है कि भाजपा के दिन अब लद गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने इस जीत पर विजयी उम्मीदवार और पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार पीडीए ने महमूदाबाद से पीडीए के पक्ष में बने माहौल का स्पष्ट संकेत दिया है। यहां के प्रत्याशी आमिर अराफात के पक्ष में पीडीए ने मतदान कर श्री अखिलेश यादव और पीडीए के बढ़ते दायरे पर मुहर लगाई है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत को मनोबल बढ़ाने वाली और भाजपा के 5वें नंबर पर आने को उप्र की भविष्य की राजनीति का सूचक बताया है।

PDA का प्रकाशस्तंभ है संविधान मानस्तंभ

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आरक्षण दिवस पर 26 जुलाई को संविधान मानस्तंभ दिवस के रूप में मनाया गया। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिला व महानगर कार्यालयों पर इस अवसर पर व्यापक आयोजन कर 'सामाजिक न्याय' व समता-समानता' और आरक्षण को बचाए-बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने इन कार्यक्रमों की अपार सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि भारत के संविधान की प्रति के सानिध्य में संविधान मानस्तंभ स्थापना दिवस को व्यापक रूप से मनाने के पीछे यही मूल भावना है कि 'संविधान मानस्तंभ वस्तुतः 'पीडीए प्रकाशस्तंभ' के रूप में हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के संकल्प का मार्ग सदैव प्रकाशित और प्रशस्त करता रहे। उन्होंने कहा कि जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है, संविधान ही कवच है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं ने जिलों में जाकर यह कार्यक्रम मनाया। सर्वश्री शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव गाजीपुर, माता प्रसाद पाण्डेय नेता विरोधी दल गोरखपुर,

लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद एटा, रामजी लाल सुमन सांसद फिरोजाबाद, अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या, धर्मेन्द्र यादव सांसद जौनपुर, श्याम लाल पाल प्रदेश अध्यक्ष बदायूं में संविधान मानस्तंभ स्थापना के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहे।

राजधानी लखनऊ में स्थापना दिवस कार्यक्रम में क्रमशः पूर्व कैबिनेट मंत्री रामगोविन्द चौधरी एवं पूर्व सांसद अन्नू टंडन शामिल हुईं। प्रदेश के अन्य जनपदों में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता संविधान मानस्तंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल रहे।

संविधान मान स्तम्भ स्थापना दिवस मनाने के लिए नामित सांसद सनातन पाण्डेय मथुरा, देवेन्द्र शाक्य हाथरस, वीरेन्द्र सिंह कानपुर महानगर, रमाशंकर राजभर इटावा, बाबू सिंह कुशवाहा झांसी, जितेन्द्र दोहरे जालौन, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद बांदा, नरेश उत्तम पटेल प्रयागराज गंगापार, एसपी सिंह पटेल फतेहपुर, धर्मेन्द्र यादव जौनपुर, राजीव राय चंदौली, छोटे लाल खरवार मिर्जापुर, पुष्पेन्द्र सरोज भदोही, अफजाल अंसारी आजमगढ़, दरोगा प्रसाद सरोज मऊ, रामप्रसाद चौधरी सिद्धार्थ नगर, उत्कर्ष वर्मा बहराइच, लालजी वर्मा बाराबंकी, नीरज मौर्या लखीमपुर खीरी, आरके चौधरी सीतापुर, आदित्य यादव बरेली, हरेन्द्र मलिक मुरादाबाद, इकरा हसन सहारनपुर के कार्यक्रमों में शामिल हुए।

इसके अलावा विधायकगण सर्वश्री त्रिभुवन दत्त आगरा, इन्द्रजीत सरोज कन्नौज, धर्मराज उर्फ सुरेश यादव हमीरपुर, संदीप पटेल कौशाम्बी, रामअचल राजभर वाराणसी, ओमप्रकाश सिंह बलिया, प्रभुनारायण यादव संतकबीरनगर, राममूर्ति वर्मा बलरामपुर, राजेन्द्र कुमार अमेठी, अताउर्रहमान संभल, इकबाल महमूद अमरोहा, मनोज पारस गाजियाबाद, महबूब अली बुलन्दशहर, कमाल अख्तर सहारनपुर के कार्यक्रमों में शामिल हुए।

एमएलसीगण, पूर्व विधायकगण और संगठन के पदाधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में शामिल हुए।

PDA सामाजिक न्याय और क्रांति का ध्वजवाहक

फाइल फोटो

जयशंकर पाण्डेय

कभी नारा लगता था जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। इस नारे को एक सन्दर्भ में बदल कर कहा जा सकता है कि जब तक न्याय नहीं होगा, धरती पर शांति नहीं होगी। उसी न्याय को प्राप्त करने के लिए संकल्पित साथियों के समूह का नाम है पीडीए। पीडीए का प्रकट रूप से पूरा नाम है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।

इसे हम इन नामों से भी बुला सकते हैं जैसे कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन या पीड़ित, दलित और असहाय। इस शब्द संक्षेप में हम उन सभी नामों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है और जो अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकते।

पीडीए की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां इस समय देश और दुनिया पर शासन कर रही हैं, वे आम आदमी को मतदाता से अधिक कुछ नहीं समझतीं। वे इस खेल में माहिर हो चुकी हैं कि किस तरह झूठ-फरेब और दमन के सहारे आम आदमी को बहलाया, फुसलाया और बरगलाया जा सकता है।

उसे कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर किसी एक पार्टी या नेता के पीछे हांका जा सकता है, कभी देश को महान बनाने के नाम पर तो कभी संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने के नाम पर उसे सालों तक नशे में रखा जा सकता है और उसके जेहन से संविधान और अधिकार भुलाए जा सकते हैं।

पीडीए राजनीति को वर्तमान में केंद्रित करने का विचार है ताकि विवादों और झूठे गौरव में फंसा कर राजनीति को भटकाया न जा सके। पीडीए नाम है एक ऐसे आन्दोलन का जो समाज के चेहरे से झूठ का पर्दा उठाकर उसे सच्चाई दिखाने के लिए सक्रिय है।

पीडीए इंसानियत को फिर से जगाकर शांति अहिंसा के पक्ष में एक आन्दोलन खड़ा करने

का नाम है। आज भले भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा कर रहा हो लेकिन यह सारा धन उन एक प्रतिशत लोगों के पास जा रहा है जो अर्थतंत्र पर हावी हैं। 146 देशों में लैंगिक समानता के लिए कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत की स्थिति 129 वें स्थान पर है। कुल मिलाकर भारत में इस समय आर्थिक असमानता की जो स्थिति है वैसी असमानता ब्रिटिश राज के दौरान भी नहीं रही।

असमानता की यह स्थिति पूरी दुनिया में निर्मित हो रही है। दुनिया के 1 प्रतिशत अमीरों के पास पूरी दुनिया की 45 प्रतिशत संपत्ति है। पिछले साल खरबपतियों का संपत्ति में 2 अरब डालर की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि सामान्य लोगों की आय या तो स्थिर रही है या फिर घटी है।

वास्तव में पीडीए की आवश्यकता स्वतंत्रता आन्दोलन और उससे निकले संविधान के सपने को पूरा करने के लिए एक विचार दर्शन और रणनीति के तौर पर पड़ी। गांधी ने जिसे सर्वोदय कहा, डॉ. राममनोहर लोहिया ने जिसे सप्तक्रांति कहा और जयप्रकाश नारायण ने जिसे संपूर्ण क्रांति कहा, उसी का ताजा संस्करण है पीडीए। पीडीए सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अभियान है।

डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में कहा था, आज से हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर राजनीतिक बराबरी कायम की जा रही है लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि देश में व्यापक तौर पर जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, अगर वह बराबरी नही मिंटाई जा सकी तो वह राजनीतिक बराबरी को लील जाएगी। आज अंबेडकर जी की भविष्यवाणी सही निकल रही है और गैर बराबरी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। आजादी के तकरीबन 79 साल के बाद भी दलितों पर अत्याचार रुका नहीं है। समाज में नए किस्म के पौराणिक आख्यानों और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बराबरी के लिए आगे आ रहे पिछड़ों को फिर से कमतर बताया जाए लेकिन उससे भी बुरी स्थिति अल्पसंख्यकों के साथ पैदा की जा रही है। अल्पसंख्यकों की राजनीति को हाशिए पर ठेल दिया गया है, उनके व्यापार के बहिष्कार की अपील की जा रही है और उनके बौद्धिकों को अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है जबकि सत्ता के साथ जुड़े लोगों के सातों खून माफ किए जा रहे हैं।

ऐसे में पीडीए उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो लोकतंत्र और संविधान के दायरे में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। जिन पर नफरती बयानों और सरकारी मुकदमों और प्रतिबंधों की गाज गिरती है समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ खड़ी मिलती है।

पीडीए का उदेश्य है समाज में नफरत फैलाने वालों के बीच प्रेम का संदेश देना है। कभी डॉ. लोहिया कहा करते थे कि अगर इस स्वतंत्रता आन्दोलन में इस देश का नेतृत्व पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हाथ में होता तो शायद देश का बंटवारा न होता इतना तो तय है कि मुस्लिम लीग का पूरा नेतृत्व जमींदारों और उच्च जाति के मुस्लिमों के हाथ में था जबकि सामान्य लोग बंटवारा नहीं चाहते थे।

आजादी के आठ दशक बाद स्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है और संघ परिवार ने अपने राजनीतिक संगठन का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया है जो अपने को पिछड़े होने का दावा करते हैं। हालांकि वे वास्तव में कितने पिछड़े हैं यह थोड़ी सी जांच पड़ताल से पता चल जाएगा। वे ही देश के समाज को नए सिरे से विभाजित करने और फिर से असमानता फैलाने का षडयंत्र कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में पीडीए उन वास्तविक वंचितों का संगठन है जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने में लगा है, संविधान को बचाने में लगा है नफरत को बचाने में लगा है और लगा है एक नए किस्म की क्रांति करने में। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर सांप्रदायिकता से कोई संगठन लड़ रहा है तो उसकी रणनीति यही है अगर दक्षिण के तमिलनाडु में कोई केंद्र के अधिनायकवाद को चुनौती दे रहा है तो उसकी भी रणनीति यही है।

पीडीए वास्तव में इंडिया का हृदय हैइसे समझिए और इसका विस्तार कीजिए, यदि इसमें जरा सी भी चूक हुई तो लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद देश के हाथ से छूट जाएगा और अराजकता की विषम परिस्थितियां पैदा होंगी। इन्हीं परिस्थितियों पर एक शायर ने लिखा है-

वह दौर भी देखा है इतिहास की आंखों ने
लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई।

(लेखक समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक हैं)

कन्नौज के साथ अन्याय कर रही भाजपा सरकार

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कन्नौज के सांसद श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज में तमाम तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे और कन्नौज के विकास के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है। श्री यादव ने ऐलान किया है कि समाजवादी सरकार बनने पर कन्नौज का ऐतिहासिक विकास किया जाएगा।

25 जुलाई को कन्नौज दौरे पर पहुंचे श्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने को श्री यादव पहले से ही संघर्षरत हैं और उन्होंने हमेशा ही कन्नौज के विकास के लिए तमाम काम किए हैं। भाजपा सरकार आने के बाद कन्नौज की तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया। श्री यादव कन्नौज पहुंचने पर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज में मोहल्ला सराय बहादुर पहुंचकर श्री राजेश पाल की माताजी के निधन पर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद पार्टी नेता कैश खां के गेस्ट हाउस पर रुककर उनका हाल-चाल जाना और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। श्री यादव ने मोहल्ला शेखाना में पूर्व नगर अध्यक्ष श्री नूरूल हसन के आवास पर पहुंचकर उनका हाल चाल जाना और उपस्थित नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

दौरे पर कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद श्री यादव ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा ने नौ साल में कन्नौज का विकास नहीं होने दिया। कन्नौज के विकास कार्यों को

रोका है। उन्होंने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सरकार बनते ही कन्नौज का ऐतिहासिक विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग जनता के बीच रहेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हर संघर्ष में खड़े रहेंगे।

उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज बनाया। सभी गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की थी लेकिन भाजपा सरकार ने सब काम रोक दिया। मेडिकल कॉलेज में कैंसर, हार्ट, किडनी, का इलाज होता। इसके लिए यहां के लोगों को दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता। यहीं कन्नौज में इलाज हो जाता लेकिन इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा कर दी। कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। परफ्यूम पार्क बंद कर दिया। मंडी की व्यवस्था खराब कर दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर वे कन्नौज को फिर विकास की बुलंदी पर ले जाएंगे और ऐतिहासिक विकास करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा शिक्षा पर हमला कर रही है। बुनियादी और प्राइमरी शिक्षा को बर्बाद कर रही है। गरीबों को शिक्षा से दूर कर षड्यंत्र कर रही है। जब स्कूल और शैक्षिक संस्थान बंद हो जाएंगे तो गरीब और पीडीए परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। भाजपा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली व्यवस्था सब कुछ बर्बाद कर दिया है। भाजपा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। खुद भाजपा के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। डिप्टी सीएम डपटे जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि सरकार में बैठे लोग अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा केवल नफरत फैलाना चाहती है। ये नकली लोग हैं। भाजपाइयों की भाषा बहुत खराब है। ये नफरत करते हैं। समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग सब जगह जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। भारत का बाजार विदेशों को दे दिया। अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा घबराई हुई है इसीलिए एसआईआर करवा रहे हैं। वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार बिहार की पूरी आठ करोड़ वोटर की लिस्ट दोबारा बन रही है। हम लोग मिलकर भाजपा को हराएंगे। भाजपा अगले चुनावों में लाखों वोटों से हारेगी। भाजपाई भी जान गए हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। भाजपा पीडीए के खिलाफ है, भाजपा गरीबों, आदिवासियों, मुसलमान भाइयों, जैन भाईयों, बौद्ध धर्म, सिख भाइयों सभी धर्मों के खिलाफ है। हिन्दुओं के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी शब्द आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी के खिलाफ लड़ने का सिद्धांत है। जब सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी तो उसमें आरक्षण होना जरूरी है।

शिक्षा

स्कूलों के विलय पर भाजपा की पिटी भद

फोटो स्रोत : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्कूल मर्जर या पेयरिंग यानि विलय के विवादित आदेश को वापस जरूर ले लिया हो मगर PDA समाज के सामने उसकी साजिशें बेनकाब हो गईं कि वह पिछड़ों, दलितों, वंचितों व शोषितों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश में लगी हुई है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कड़े रुख और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी किसी स्कूल को बंद किया जाए उसके परिसर में सपा की ओर से PDA पाठशाला शुरू करने के उनके ऐलान पर भाजपा जरूर घबड़ा गई है और भारी दबाव के बाद उसे अपना आदेश रद्द करना पड़ा मगर उसकी नीयत से अंदेशा बना हुआ है कि अगर ये लोग सत्ता में रहे तो एक न एक दिन ये फिर ऐसी ही कोई न कोई साजिश रचेंगे इसलिए पीडीए समाज ने अब भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का निर्णय ले लिया है।

यह पहली बार नहीं है कि भाजपा ने पीडीए के खिलाफ साजिश रची हो। पहले भी वह पीडीए समाज को दबाने, कुचलने के लिए इस तरह के निर्णय करती रही है। नौकरियों से आरक्षण समाप्त करना उसकी पुरानी मंशा है।

इसे पूरा करने के लिए वह निजीकरण का बहाना तलाश रही है क्योंकि भाजपा को पता है कि बाबा साहब डा भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ों, दलितों, वंचितों को संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए हैं, उसे सरकारी नौकरियों में खत्म करने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर लगातार विरोध के कारण भाजपा अब सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपकर आरक्षण को खत्म करने पर तुली हुई है।

इसी कड़ी में यूपी की भाजपा सरकार ने पीडीए समाज की शिक्षा पर हमला बोला है। उसे मालूम है कि पीडीए समाज शिक्षित होकर अपने अधिकारों क बात करेगा इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए। उसने यूपी के करीब 27000 स्कूलों के मर्जर या पेयरिंग के बहाने बंद करने का फैसला किया।

इसके पीछे उसकी मंशा थी कि स्कूलों के दूर हो जाने से गरीब बच्चे स्कूल न जा सकें और हमेशा अशिक्षित रहते हुए अपने अधिकारों के बारे में न जान पाए। आदेश पर अमल शुरू भी हो गया था मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए समाज के

भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा उजागर

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के कड़े विरोध के बाद स्कूलों का मर्जर या पेयरिंग का आदेश वापस लेने के भाजपा सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही भाजपा सरकार का नया फरमान उसकी शिक्षा विरोधी नीति की नैतिक हार है। यह पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने आठ साल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। भाजपा सरकार साजिश के तहत पीडीए और गरीबों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। समाजवादी लोग भाजपा की शिक्षा विरोधी षड्यंत्रकारी नीति को सफल नहीं होने देंगे। भाजपाई, कान खोल कर सुन लें और आंख खोल कर देख लें। हम बच्चों के शिक्षा के अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे।

श्री यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादियों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने के लिए शुरू की गई पीडीए पाठशाला को छात्रों और अभिभावकों से मिल रहे भारी जनसमर्थन से भाजपा सरकार घबरा गई है। इसी के चलते सरकार बैकफुट पर है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का शिक्षा विरोधी चेहरा इसी से उजागर हो रहा है कि एक तरफ वह शिक्षा से वंचित करने का कार्य कर रही है दूसरी तरफ पीडीए पाठशाला संचालित करने वाले समाजवादियों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रही है। शिक्षा देने जैसा पवित्र कार्य कर रहे लोगों पर फर्जी एफआईआर करा रही है।

श्री यादव ने कहा कि शिक्षा और शिक्षण कार्य सबसे महान होता है। इसी से देश और समाज का विकास होता है लेकिन भाजपा सरकार समाज को पीछे ले जाना चाहती है। तरह-तरह के अवरोध खड़ा कर बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है। समाजवादी पार्टी इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

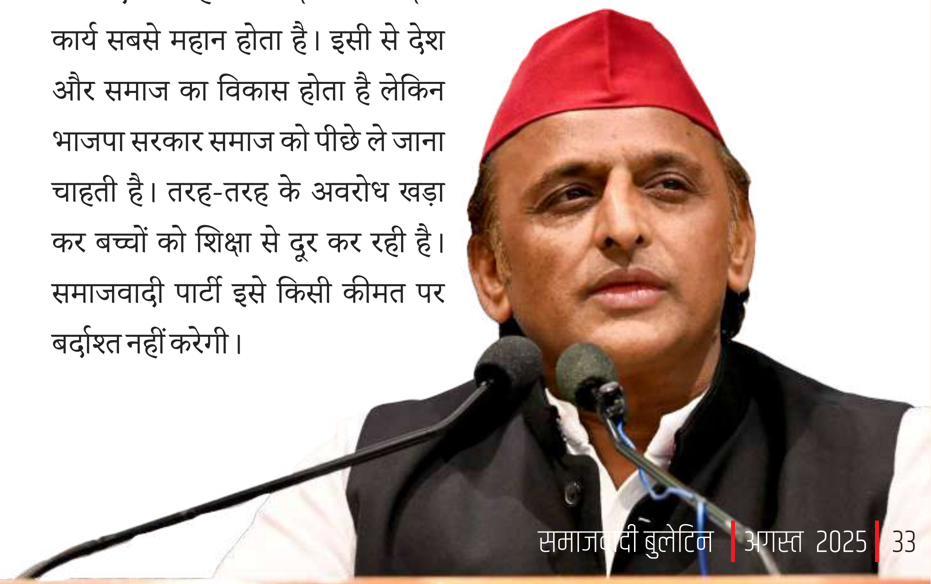

अगुआ श्री अखिलेश यादव सरकार के इस फैसले के खिलाफ डटकर खड़े हो गए।

श्री अखिलेश यादव के कड़े तेवर को देखते हुए भाजपा सहम गई। बाद में श्री अखिलेश यादव ने उन गांवों में पीडीए पाठशाला शुरू करने का ऐलान कर दिया जहां स्कूल बंद हो रहे थे। तमाम जगहों पर पीडीए पाठशाला शुरू भी हो गई जिसपर भाजपा सरकार घबरा गई।

समाजवादी पार्टी ने सड़क से सदन तक इस मसले को उठाया। पीडीए पाठशाला के आंदोलन के साथ ही मानसून सत्र में भी यह मुद्दा गूंजा और जब भाजपा सरकार को लगा कि स्कूल बंद होने पर समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन शुरू कर देगी इसलिए उसने मर्जर व पेयरिंग के अपने फैसले का रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

फिलहाल यह आदेश रद्द हो गया है लेकिन भाजपा की भद पिट चुकी है। पीडीए समाज भी पीडीए की नीति, नीयत और साजिश से वाकिफ हो चुका है और उसे अब पता चल गया है कि अगर भाजपा सत्ता में रही तो उसके खिलाफ ऐसी ही साजिश होती रहेगी इसलिए अब पीडीए ने 2027 में भाजपा को हटाने का निर्णय ले लिया है।

संवैधानिक दायित्व से मुंह मोड़ती भाजपा

फोटो स्रोत : गूगल

मनोज काका

भाजपा सरकार ने जिस तरह पेयरिंग और मर्जर के नाम पर यह कुतर्क गढ़ा कि गांव में बच्चों की संख्या कम है इसलिए दूर का स्कूल अच्छा कर दिया जाए या किसी बड़े विद्यालय में मिला दिया जाए, यह सोच न केवल आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून) की भावना के विपरीत है बल्कि ग्रामीण और वंचित समुदायों के बच्चों से उनका सबसे ज़रूरी अधिकार छीनने जैसा है।

बच्चों की संख्या घटने के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं मगर उसका समाधान स्कूल छीनना नहीं हो सकता है। सरकार ने भले ही यह आदेश रद्द कर दिया हो मगर सवाल अभी खड़ा है कि आखिर भाजपा ने यह नासमझी दिखाई क्यों? इसके पीछे भाजपा की मंशा, नीयत पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है और इसमें साजिश की बू आना स्वाभाविक है।

RTE (शिक्षा का अधिकार कानून) कोई प्रशासनिक गाइडलाइन नहीं बल्कि एक संवैधानिक गारंटी है जोकि बच्चों को नजदीकी स्कूल, प्रशिक्षित शिक्षक और

मूलभूत सुविधाओं के साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसलिए सरकार द्वारा नजदीक के स्कूल में संसाधन समृद्ध होने की बात के आधार पर स्कूल की पेयरिंग शिक्षा के अधिकार को बच्चों से अलग नहीं कर सकता।

दरअसल, एक दूरस्थ गांव की दो बच्चियों के लिए भी अगर एक स्कूल चलता है तो वह सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होता है। ऐसे में पेयरिंग या मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करना नीतिगत नासमझी ही नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ने जैसा है।

गौर करने लायक तथ्य यह है कि मर्जर के बजाय सरकार को सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या पर विचार करना चाहिए था। यह विचार तब और लाजिमी हो जाता है जब सरकार खुद संसद में यह आंकड़ा पेश करती है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में इजाफा एक अहम कारण है। बीते दिनों खुद सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2014-15 से 2023-24 तक के बीते एक दशक में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है लेकिन निजी स्कूलों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई है।

निजी स्कूलों की बात करें तो 10 राज्यों ने निजी स्कूलों की संख्या में राष्ट्रीय वृद्धि के 14.9% प्रतिशत को पार कर लिया है। 2014-15 से 2023-24 की अवधि में उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 77,330 से बढ़कर 96,635 हो गई है, जो 24.96% की वृद्धि है।

यू डाइस प्लस की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में उत्तर प्रदेश में 4.44 करोड़ छात्रों का नामांकन दिखाया गया था जोकि नवीनतम आंकड़े के अनुसार 28.26 से घटकर 4.16 करोड़ रह गया है।

स्कूलों में कम नामांकन के कई और कारण भी हैं मसलन भारत में 14.71 लाख से अधिक स्कूलों में से 1.52 लाख में विद्युत् की सुविधा नहीं है जिससे शिक्षकों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग में बाधा आ रही है।

मर्जर के बजाय सरकार को सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या पर विचार करना चाहिए था। यह विचार तब और लाजिमी हो जाता है जब सरकार खुद संसद में यह आंकड़ा पेश करती है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में इजाफा एक अहम कारण है

67000 स्कूलों, जिनमें 46000 सरकारी स्कूल शामिल हैं, कार्यात्मक शौचालयों का अभाव है। केवल 3.37 लाख सरकारी स्कूलों (33.2%) में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय हैं जिनमें से एक तिहाई से भी कम क्रियाशील हैं। केवल 43.5% सरकारी स्कूलों में शिक्षण के लिए कंप्यूटर हैं जबकि निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में यह संख्या 70.9% है। इसके अलावा भारत में लगभग एक लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में केवल एक शिक्षक है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है, खासकर लड़कियों के मामले में। यहां लगभग 14 प्रतिशत छात्राएं प्राथमिक विद्यालय और 3 1 प्रतिशत छात्राएं माध्यमिक विद्यालय छोड़ देती हैं जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लक्ष्य के अनुसार 2030 तक स्कूल स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) हासिल करना चाहती है। फिर भी उत्तर प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्यों में सरकारी स्कूलों के बंद होने का काम बदस्तूर जारी है।

स्कूल न जाने की स्थिति में बच्चे न केवल सामाजिक रूप से पिछड़ जाएंगे अपितु आर्थिक रूप से भी अपंग हो जाएंगे जिससे आने वाले समय में वे समाज, माता-पिता पर एक भार के रूप में देखे जाएंगे जिससे उनमें हिंसा, लूट, चोरी, अपहरण, नशाखोरी की आदतों का विकास हो जाएगा जिससे सभ्य समाज की परिकल्पना को धक्का लगेगा और अपराध में वृद्धि होगी।

शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच देना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए इस बात की अनुशंसा कोठारी आयोग ने की थी और नई शिक्षा नीति 2020 भी इस बात की पुरजोर वकालत करती रही है।

भाजपा सरकार के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की घटती लोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण बड़ी संख्या में नए प्राइवेट स्कूलों का खुलना है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर अनुप कुमार राजपूत कहते हैं, "प्राइवेट स्कूलों की

सांसद डिंपल जी ने प्रशासन से पूछे तीखे सवाल

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा सरकार के स्कूलों के विलय या बंद करने के आदेश के बाद मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव मुखर हुईं और प्रशासन से सवालों की झड़ी लगा दी तो हड़कंप मच गया। श्रीमती यादव ने प्रशासन से लिखित में ऐसे तीखे सवाल पूछे कि प्रशासन को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने मैनपुरी जिला प्रशासन से 7 सवाल पूछकर उन्हें परेशानी में डाल दिया।

इन सवालों का अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं था। समाजवादी पार्टी के भारी दबाव के बाद जब सरकार ने यू टर्न मारते हुए आदेश को रद किया तो मैनपुरी जिला प्रशासन ने राहत की सांस लीं।

भाजपा सरकार ने जैसे ही स्कूलों को बंद करने, मर्जर आदि का अव्यवहारिक फैसला सुनाया, श्रीमती डिंपल यादव बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश के खिलाफ डटकर खड़ी हो गईं। उन्होंने 17 जुलाई को जिलाधिकारी को इस बाबत पत्र लिखा और उनसे 7 तीखे और गंभीर सवाल पूछे।

उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा कि जनपद मैनपुरी में 943 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 341 विद्यालयों को बंद करने या अन्य विद्यालयों में मर्ज अथवा पेयर करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय हजारों बच्चों और उनके परिवारों को सीधा प्रभावित करेगा।

श्रीमती डिंपल यादव ने यह भी प्रश्न किया कि जिन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, उनके शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, रसोइयों एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए तथा यह भी जानना चाहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए।

मैनपुरी की जनता के हितों के लिए पूछे गए इन सवालों का कोई माकूल जवाब प्रशासन के पास नहीं था।

सपा ने सड़क से सदन तक भाजपा को घेरा

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के स्कूल मर्जर या पेयरिंग के अव्यवहारिक, अविवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सड़क से सदन तक भाजपा सरकार को घेरा।

भाजपा सरकार को आदेश वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया।

समाजवादी पार्टी के सांसदों धर्मेन्द्र यादव, नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, नीरज मौर्य, सुश्री प्रिया सरोज ने 30 जुलाई को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के बंद करने और मर्जर का मामला जोर-शोर से उठाया।

लोकसभा में श्री धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि एक तरफ जहां देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अलग तरह का सामंतवाद है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता है लेकिन उत्तर प्रदेश में 26 हजार 12 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। इसे उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा।

उधर मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा और बच्चों के हितों का मुद्दा गंभीरता से उठाते हुए भाजपा सरकार के फैसले का गलत ठहराया।

मान्यताएं हो रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो राज्य उन स्कूलों को मान्यता देता है, वह स्कूल की मॉनिटरिंग भी करे। शिक्षा एक क्षेत्र है जो कि नीतिगत और दिशानिर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए।"

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के पूर्व डीन प्रो अनिल सद्गोपाल कई कारणों की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं, "सरकारी स्कूलों की बढ़ती हुई बदहाली, पर्याप्त शिक्षकों और कमरों की कमी, शिक्षकों को अक्सर गैर-शैक्षिक कार्यों में लगाना, 70 फीसदी प्राथमिक स्कूलों व 55 प्रतिशत मिडिल स्कूलों में छह साल से प्रधान शिक्षकों का न होना, तीन चौथाई में बिजली न होना, पाठ्यपुस्तकें देर से मिलना, इन जैसी वजहों से ही बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं।"

महान समाजवादी चिंतक डा राम मनोहर लोहिया ने ऐसी पांच प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिससे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। पांच असमानताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने 5 क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में उनके द्वारा दो और क्रांतियों को जोड़ा गया। सात क्रांतियां या सप्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थीं। उत्तर प्रदेश में परियोजना के नाम पर 27000 से अधिक विद्यालयों से उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों, विशेषकर बच्चियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की असमानता के विरोध में समाजवादी पार्टी डा लोहिया के दिखाए सप्त क्रांति के रास्ते पर चलते हुए अपना पुरजोर विरोध करने से पीछे नहीं रही।

बच्चा स्कूल न जाए तो स्कूल को बच्चों के पास चले जाना चाहिए। इस अवधारणा पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने PDA पाठशाला का ऐलान किया तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी बात पहुंची और शिक्षा के महत्व के बारे में उसे प्रेरणा मिली और आवाज मुखर हुई। इस मुखर आवाज का नतीजा भी सामने आया और भाजपा को कदम पीछे खींचने पड़े।

बच्चा स्कूल न जाए तो स्कूल को बच्चों के पास चले जाना चाहिए। इस अवधारणा पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने PDA पाठशाला का ऐलान किया तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी बात पहुंची और शिक्षा के महत्व के बारे में उसे प्रेरणा मिली और आवाज मुखर हुई

श्री अखिलेश यादव ने शिक्षा के महत्व के बारे में जो कदम उठाया, वह पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के विचारों को भी आगे बढ़ाने वाला है क्योंकि नेताजी, डॉ. राम मनोहर लोहिया का 'रोटी कपड़ा सस्ती हो-दवा पढ़ाई मुफ्त हो' के नारे को हमेशा सार्थक करते रहे। अपने मुख्यमंत्री काल में इसे यूपी में उन्होंने लागू भी किया। लड़कियों की शिक्षा इंटर तक मुफ्त की। बाद की सरकारों ने भी उसे आगे बढ़ाया। श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुतेरे कदम उठाए, लैपटाप तक बांटे और तमाम योजनाएं लागू कीं।

समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई को धार देने में जुटे हुए हैं। श्री अखिलेश यादव का विजन बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी सोच यही बताती है कि-

राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान
बिरला या गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान ॥

जिस पार्टी के मुखिया की शिक्षा को लेकर इतनी स्पष्ट नीति और नीयत हो, वह कभी भी पीडीए समाज को शिक्षा के महरूम नहीं होने देगा। श्री अखिलेश यादव के रहते पीडीए समाज के खिलाफ होने वाली हर साजिश अब तक नाकाम हुई और आगे भी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने पाएगी।

(लेखक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं)

सपा के रीजन डाक्यूमेंट ने भाजपा के विजन की पोल खोली

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा सरकार ने झूठे सपने दिखाने वाले 2047 विजन डाक्यूमेंट पर विधानसभा में चर्चा के जरिये जनता को फिर गुमराह करने की कोशिश की मगर समाजवादी पार्टी ने रीजन डाक्यूमेंट जारी कर भाजपा की पोल खोल दी।

समाजवादी पार्टी ने भाजपा से 47 सवाल पूछकर विजन 2047 के विजन डाक्यूमेंट पर ऐसा घेरा कि पूरी भाजपा सरकार निरुत्तर हो गई। विधानमंडल के मानसून सत्र में भाजपा बुरी तरह घिरी और हर सवालों पर भागती और कुतर्क गढ़ती नजर आई।

जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा ही मुखर रही है। इस बार मानसून सत्र को केवल 4 दिन का बुलाकर भाजपा सरकार ने बचने की कोशिश की मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की बनाई रणनीति के सामने उसके लिए यह 4 दिन भारी पड़ गया। भाजपा सरकार ने केवल प्रचार पाने के लिए और आदत के मुताबिक जनता को दूसरे जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए तथाकथित विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में 13 अगस्त से लगातार 24 घंटे की चर्चा चलाने का ऐलान किया जिसका न तो कोई तुक था और न ही जनता को लाभ। इस 24 घंटे की चर्चा में न जनता की आज की तकलीफों पर कोई बात नहीं हुई। 20 साल बाद के सपने दिखाए गए जबकि नौजवान, किसान, व्यापारी आज की तकलीफों का निदान चाहता है।

समाजवादी पार्टी ने लोगों की तकलीफों को उठाया। बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, स्कूलों की चौपट होती व्यवस्था, धराशाई हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भाजपा सरकार के विजन को जानने चाहा पर भाजपा ने आज के बजाय 2047 में यूपी कैसा होगा, इसपर बात की। इस 24 घंटे की चर्चा की पोल तब और खुल गई जब भाजपा सरकार के कुछ मंत्री ही सदन में सोते हुए

देखे गए। खुद भाजपा विधायकों ने भी कोई खास रूचि नहीं दिखाई। नतीजा, 24 घंटे का सत्र औपचारिकता बनकर रह गया और जनता के हितों पर कोई सार्थक बात नहीं हुई।

इसके विपरित सपा ने 2017 और 2022 के भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में पूछा कि उसने जनता से कितने वायदे पूरे किए। इस सवाल पर भाजपा कतराने लगी और दाएं-बाएं कर निकलने की कोशिश की मगर समाजवादी पार्टी सदस्यों ने सरकार को घेरा तो हमेशा ही तरह भाजपा ने दूसरे मुद्दे छेड़कर इन जरूरी सवालों को टाला।

इससे पहले 1 1 अगस्त से शुरू हुए विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार से जनता के सवालों का जवाब न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार में PDA की हकमारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष श्री माता प्रसाद को उनके गोरखपुर यात्रा के दौरान भाजपा के लोगों द्वारा अपमानित करने के वाकए को भी सपा ने जबरदस्त तरीके से उठाया।

11 अगस्त से विधानमंडल का सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी ने जनता के सवालों को जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति बनाई ताकि आम जनता को राहत दिलाई जा सके। सरकार ने सवालों से बचने के लिए सत्र को महज 4 दिन का रखा और इसे तब और हास्यास्पद बना दिया जब एक दिन 24 घंटे तक विधानसभा चलाने का फैसला किया गया।

अब जनता सवाल कर रही है कि इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी कि उसे काम करने के लिए 24 घंटे जागने की जरूरत पड़ी। वह भी 2047 में प्रदेश कैसा होगा, इसपर चर्चा के लिए 24 घंटे ज़ाया किए गए जबकि बात आज की होनी चाहिए थी। जाहिर है, सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब उसे रात-दिन जागकर काम करने का दिखावा करने की जरूरत पड़ी ताकि जनता को गुमराह किया जा सके।

सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय किया गया कि जनता के सवालों, उनके हितों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाना है क्योंकि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से आंखें बंद किए हुए है।

सत्र शुरू होने पर पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और मर्जर करने, खाद की समस्या, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, वोट चोरी के विरोध और बाढ़ की समस्या को लेकर सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए।

बात न सुनी जाने और सरकार द्वारा जवाबदेही से भागने पर सपा विधायकों ने विधानभवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर- प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक लालटोपी लगाकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर धरने में शामिल हुए। ये विधायक नेता विरोधी दल विधानसभा श्री माता प्रसाद पाण्डेय, नेता विरोधी दल विधान परिषद श्री लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में धरना पर बैठे।

ये सभी विधायक जनता के सवालों को तख्तियों पर लिखकर लाए थे। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों के जनसरोकारोंं पर तीखे तेवरों को देखते हुए भाजपा सरकार भी घबरा गई है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है इसलिए वे इधर-उधर की बातें कर जनता का ध्यान बांटने में जुट गए हैं जैसा कि भाजपा की पुरानी फितरत है मगर समाजवादी पार्टी और उसके विधायक जनहित के मुद्दों पर सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं।

किसान और आम इंसान
भाजपा राज में सब परेशान

फोटो स्रोत : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में किसान, नौजवान, व्यापारी समेत आम इंसान परेशान और बेहाल हैं। यूपी में कानून-व्यवस्था से लेकर खाद-बीज, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं को बुरा हाल है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और लोगबाग त्रस्त हो गए हैं मगर भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार में ही खींचतान मची हुई है।

यूपी के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मंत्रियों को सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। सरकार में कुर्सी को लेकर मचे घमासान का असर आम आदमी पर पड़ रहा है। आमजन अब 2027 को इंतजार कर रहे हैं ताकि चुनाव हो और भाजपा सरकार की विदाई की जा सके।

भाजपा सरकार ने किसानों के सामने संकट पैदा कर दिया है। किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रही है। खरीफ की फसल विशेष कर धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। किसान को फसलों के लिए डीएपी, यूरिया की जरूरत है लेकिन प्रदेश के जिलों-जिलों में खाद का संकट है। सहकारी समितियों में खाद नहीं है। निजी विक्रेता कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और ओवर रेटिंग कर रहे हैं।

विभाग और सरकार की लापरवाही और लचर रवैये से किसान मारा-मारा फिर रहा है। पुरुष किसानों के साथ-साथ महिलाओं को भी खाद के लिए सुबह से ही सहकारी समितियों पर लाइन लगानी पड़ रही है। किसानों का दर्द तब और बढ़ जाता है जब खाद के बजाय उन्हें पुलिस की लाठियां और प्रताड़ना मिलती है।

लखीमपुर खीरी के श्रीनगर की बहुउद्देशीय सहकारी समिति संकर भदुरा में 16 जुलाई को किसानों को खाद नहीं मिली। अलबत्ता पुलिस ने महिला-पुरुष किसानों पर लाठीचार्ज जरूर कर दिया जिसमें तमाम किसान घायल हुए। दूसरे जिलों का भी यही हाल है। हाथरस जिले में कई सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया नहीं है। गोंडा जिले में कई समितियों में सिर्फ कागज पर खाद है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी है। गरीबों, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीजों को दर-दर भटकना पड़ता है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मानक के अनुरूप सुविधाएं नहीं हैं। मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है। समाजवादी सरकार में मरीजों को सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। भाजपा सरकार ने उसे भी बर्बाद कर दिया।

कई जिलों में मेडिकल कॉलेज के नाम पर भवन खड़े हैं, वहां पर पर्याप्त प्रोफेसर,

बिजली संकट से जनता त्रस्त

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रस्साकशी ने बिजली व्यवस्था को चौपट कर दिया है। शहरी और गांवों के इलाके बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बिजली कटौती का आलम यह है कि ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो जा रही है। अब यह चर्चा आम हो चली है कि बिजली संकट को जानबूझकर दिखाया जा रहा है ताकि निजीकरण का माहौल बन सके और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

बिजली संकट से हालात कितने खराब हो चुके हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक मंत्री को खुद ट्रांसफार्मर बदलवाने जाना पड़ रहा है। बिजली कटौती से लोगबाग इतने त्रस्त हैं कि 2027 में वे भाजपा की बत्ती गुल करने को तैयार बैठे हैं।

यूपी में भाजपा सरकार के बनने के बाद से अब तक उत्पादन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

ऊर्जा मंत्री खुद अफसर रहे हैं मगर उनके विभाग में ही अफसर उनकी नहीं सुनते। मुरादाबाद दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में बिजली मंत्री की मौजूदगी में बिजली का गुल होना इसका ताजा उदाहरण हैं। बस्ती में एक अधिकारी द्वारा एक उपभोक्ता के साथ बदतमीजी का आडियो वायरल होने के बाद स्थिति हास्यास्पद हो गई।

हाल ही में यूपी सरकार के मंत्री ने सीतापुर जनपद में जब एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जेई से कहा तो उसने उन्हें ही सलाह दे दी कि आप जाकर बदलवा दीजिए। मंत्री वहां पहुंचे और उन्हें धरना देना पड़ा। ट्रांसफार्मर बदलवाना पड़ा। अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्रियों का धरना देना बताता है कि सरकार में जबरदस्त खींचतान है। सरकार से लेकर अफसर तक बेलगाम हो चुके हैं।

शहरों और गांवों में अघोषित बिजली कटौती ने जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश में बिजली नहीं, केवल बिजली का बिल आ रहा है और ये बेइंतहा बिल लोगों की जेबें खा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी कार्य किए थे, भाजपा सरकार ने 9 साल में सब बर्बाद कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सरकार सिंचाई के लिए भी किसानों को बिजली नहीं दे पा रही। राजधानी लखनऊ का आलम यह है कि यहां विभिन्न इलाकों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। बिजली के लिए जब राजधानी लखनऊ के लोग धरना देने पर मजबूर हो तो प्रदेश के अन्य जिलों और ग्रामीण इलाकों में हालात कितना बुरा होगा इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है।

डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ और जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। कई जिलों के मेडिकल कॉलेज केवल रेफर सेंटर बन कर रह गए हैं। समाजवादी सरकार ने मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधा के लिए लोहिया संस्थान, कैंसर संस्थान जैसे बड़े-बड़े अस्पताल बनवाए। केजीएमयू और पीजीआई जैसे संस्थाओं में सुविधाएं बढ़ाई थीं लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकाल में सुविधाओं को नहीं बढ़ाया। हालात ऐसे हैं कि भाजपा सरकार ने 9 साल में जिलास्तर का एक भी अस्पताल नहीं बनाया।

नौजवानों को रोजगार देने में भी भाजपा सरकार नाकाम है। भाजपा ने छात्रों, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। छात्रों, युवाओं के पास नौकरी, रोजगार नहीं है। भाजपा सरकार ने सभी विभागों की नौकरियों को संविदा और आउटसोर्स करके नौजवानों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है।

भाजपा सरकार का पूरा ध्यान निजीकरण के जरिये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने पर है। भाजपा के पास युवाओं के भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह फेल है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला हो या मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में, हर जगह युवा अपमानित किये जा रहे हैं। हक की मांग करने पर सरकार पुलिस से लाठीचार्ज कराकर युवाओं की आवाज दबा देती है।

कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पूरी तरह फेल है। खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों में कानून का डर नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी खुलेआम हत्याएं हो रही है।

शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्षों की मिसाल

-अखिलेश

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने 12 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची होते हुए रामगढ़ के निमरा पहुंचकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरू स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने श्री हेमंत सोरेन की माताजी श्रीमती रूपी सोरेन और उनकी पत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों से भी भेंट की।

रांची पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्री शिबू सोरेन जी ने आदिवासी भाई-बहनों की परेशानी और उनके साथ हुए अन्याय को समझा। उन्होंने आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। शिबू सोरेन जी ने अपने जीवन में एक पार्टी खड़ी की। नया प्रदेश बनाने के लिए संघर्ष किया। श्री शिबू सोरेन जैसा नेता बनना बहुत मुश्किल

है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को विरासत में एक विचारधारा मिली और पिता का लंबा संघर्ष उनके साथ है। हमें उम्मीद है कि श्री हेमंत जी उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता से मतदान का अधिकार छीनना चाहती है। भाजपा के लोग हकमारी तो करते ही हैं, अब मतमारी कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने ये लोग बड़े पैमाने पर वोटों की हेरफेर करना चाहते हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से ली गई है। अंग्रेजों की तरह भाजपा भी फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती है। हिन्दू-मुसलमान के बीच नफरत फैलाती है। सामाजिक सद्भाव खराब करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों के हक, किसानों, नौजवानों की बात करती है। नौकरी रोजगार, विकास की बात करती है।

एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि फतेहपुर की घटना के लिए सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी को जेल भेजना चाहिए। जिलाधिकारी और एसपी ने अगर कार्रवाई नहीं की है तो सरकार उन्हें तत्काल हटाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। अराजकता का माहौल है।

उत्तर प्रदेश में कोई भी और कुछ भी सुरक्षित नहीं है। विकास कार्य नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी, भ्रष्टाचार, खाद की किल्लत, किसानों की समस्या से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के लोग षडयंत्र के तहत प्रदेश में सामाजिक सौहार्द खत्म कर रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि फतेहपुर में घटी घटना, तेज़ी से ख़त्म होती भाजपा की निशानी है। जब-जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी। उन्होंने कहा कि देखना ये है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली वालों के ड्रोन।

जनेश्वर जी
समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती 5 अगस्त को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों एवं अन्य प्रदेशों में मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में हुआ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट स्थित उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर नमन किया गया।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्री जनेश्वर मिश्र जी ने जीवनपर्यंत समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया था, उसी से देश और समाज में खुशहाली आएगी। समाजवादी सिद्धांतों और कार्यक्रमों से हर वर्ग को सम्मान मिलेगा। हमारे नेताओं ने हम समाजवादियों को जो विचारधारा दी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, उसे और आगे लेकर जाएं। समाजवादी सिद्धांतों पर चलकर ही देश मजबूत होगा। देश की सीमाएं मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि आज हम जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। हम सभी संकल्प लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करेंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बताए कि जब 2014 में वह सरकार में आई थी तब देश का क्षेत्रफल कितना था और अब देश का क्षेत्रफल कितना है। भाजपा सरकार जब ये जवाब दे दे तब तिरंगा लेकर घूमे। जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी सरकार ने सबसे बड़ा तिरंगा झंडा लहराया था। यहां पर पीएसी, पुलिस के बैंड समय-समय पर परेड करते थे। तिरंगा के दुश्मन लोगों ने परेड बंद करवा दी।

श्री जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर उनके परिवार के सदस्यों श्रीमती मीना तिवारी, विश्वभूषण, चंद्रशेखर तिवारी, तारकेश्वर मिश्र सहित राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी, सांसद सनातन पाण्डेय, पूर्व नेता विरोधी दल विधानसभा रामगोविन्द चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल आदि ने श्री जनेश्वर मिश्र को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

फूलन देवी

अन्याय और शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज

बुलेटिन ब्यूरो

सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्षरत पूर्व सांसद श्रीमती फूलन देवी जी की जयंती 10 अगस्त को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया सभागार में, विधायक दल की बैठक में मनाई गई।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि फूलन देवी जी ने अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए जीवनपर्यंत संघर्ष किया। सभी विधायकों ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इससे पहले फूलन देवी का शहादत दिवस 25 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ सहित प्रत्येक जनपद में सादगी से मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष को याद किया।

लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने वीरांगना फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि फूलन देवी अन्याय, अत्याचार के कारण बागी बनीं और श्रद्धेय नेताजी ने फूलन देवी को सांसद बनाकर उन्हें पहचान दी। फूलन देवी का इतिहास क्रांतिकारी रहा है। वह कभी अन्याय, अत्याचार के सामने नहीं झुकीं। फूलन देवी मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुईं। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उन पर लगे सभी आरोप वापस लेकर उनकी रिहाई कराई थी। पिछड़ी जाति की फूलन देवी सामाजिक जीवन में अपमानित होने के कारण ही बागी बनी थीं।

कार्यक्रम में डॉ. मधु गुप्ता पूर्व एमएलसी, मीरावर्धन पूर्व मेयर प्रत्याशी, अरविन्द कुमार सिंह पूर्व सांसद, डॉ. राजपाल कश्यप पूर्व एमएलसी, शशांक यादव पूर्व एमएलसी, जूही सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा, अवलेश सिंह सचिव, मनोज यादव प्रवक्ता आदि ने भी वीरांगना फूलन देवी को श्रद्धांजलि दी।

साफ़ और बेबाक X

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

अपने हक़ और इंसाफ की ख़ातिर लड़ेंगे
अब ज़ुल्मों की हर बंदिश हम पार करेंगे!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

चुनाव आयोग पहले पिछले एफ़िडेविट्स का जवाब दे जब हमने 18 हज़ार वोट कटने पर, शपथपत्र दिये थे। चुनाव आयोग बताए उस मामले में क्या कार्रवाई हुई?

चुनाव संबंधित मामलों और मसलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, **फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट** की आवश्यकता है। यहाँ भी समयबद्ध कार्यवाही और कार्रवाई होनी चाहिए, तब ही लोकतंत्र बचेगा। चुनाव आयोग में क्या कोई सिटीज़न चार्टर नहीं होता है।

चुनाव आयोग गति के संबंध में कच्छप का प्रतिद्वंद्वी न बने।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

बच्चे-बच्चे ने पुकारा 'पीडीए पाठशाला'
हम सबके 'उज्ज्वल भविष्य' का सहारा!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

अपना मत, अपनी हिम्मत!

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 1d

फतेहपुर में घटी घटना, तेज़ी से ख़त्म होती भाजपा की निशानी है।

जब-जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गयी है। अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी।

देखना ये है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख़्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्लीवालों के ड्रोन।

सामाजिक एकता ज़िंदाबाद!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना, 'पीडीए पाठशाला' आंदोलन की महाजीत है।

शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की ये नैतिक हार है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अयोध्या- फ़ैज़ाबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु प्रदान करे।

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 6d

भाजपा S.I.R को लागू करके संविधान का ही विरोध कर रही है। जबकि हमारे द्वारा S.I.R का विरोध 'संविधान' को ही बचाने की कोशिश है। ये हारती हुई भाजपा की निशानी है। जनता भाजपा के ख़िलाफ़ वोट न डाल सके, इसीलिए वो जनता से वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है।

वर्चस्ववादी भाजपा की एकतंत्री विचारधारा में चुनाव की अवधारणा है ही नहीं। वहाँ तो मनमर्ज़ी का मनोनयन चलता है।

घोर निंदनीय!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

@ दिल्ली

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 6d

इसकी गहरी जाँच-पड़ताल हो कि 'नशा' उप्र भाजपा सरकार की 'मुख्य प्राथमिकता' क्यों है?

शराब हो या नशे का कोई और रूप, इस भाजपा सरकार में आख़िरकार वो तीव्र गति से क्यों फलफूल रहा है?

नशा परिवार तोड़ता है लेकिन ये बात परिवारवाले ही समझ सकते हैं।

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

जब 'रक्षा बंधन' का त्यौहार आता है
सबके जीवन में स्नेह-सौहार्द लाता है

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

उत्तरकाशी के धराली में जो तबाही हुई है उसके पीछे प्रकृति के साथ कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा किया जा रहा दुर्व्यवहार ही मूल कारण है।

हमारी मांग है कि बचाव और राहत का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए और लोगों के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। हर एक जीवन अनमोल है।

पर्यावरण संरक्षण ही जीवन सरंक्षण की प्रतिभूति होता है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

भाजपा किसी की सगी नहीं है।

और कुछ नहीं कहना है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

उनको हमारी भावभीनी 'अंतिम जोहार'
जिन्होंने किया 'झारखंड का निर्माण' !

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

प्रयागराज के नाम पर 20 हज़ार करोड़ का स्मार्ट सिटी का जो फंड भाजपाई निगल गये, अगर **'महाकुंभ के उस महाकोष'** का एक अंश भी सीवर और नाला सफ़ाई में लग जाता तो प्रयागराज का ये थाना आज तालाब न बनता।

ये भाजपाई भ्रष्टाचार है जो बाढ़ बनकर प्रयागराज में घर-घर तक पहुँच गया है।

भाजपा जाए तो सब कुछ सुधर जाए!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक जी का निधन, अत्यंत दुःखद !

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।

शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।

भावभीनी श्रद्धांजलि !

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

World Lion Day की सबको शुभकामनाएँ और इटावा लायन सफ़ारी में शेरों की बढ़ती हुई आबादी के लिए सभी सच्चे-अच्छे संरक्षकों को बधाई।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

भाजपा को समर्पित, साभार वसीम बरेलवी जी :

मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ,
मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है
...

अंदर-ही-अंदर टूटा जा रहा है
टकराहट में हाथ छूटा जा रहा है
डबल इंजन द्वारा देश लूटा जा रहा है
आपस में एक-दूजे को कूटा जा रहा है
भाजपाइयों को देखते ही लोग कहते हैं,
वो देखो-वो देखो 'महा-झूठा' जा रहा है...

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
Translate post

जो इतिहास में उलझे हैं, वो क्या विज़न की बात करेंगे।

भाजपाई पहले अपना मैनिफेस्टो उठाकर देखें कि उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। दरअसल भाजपा को मैनिफेस्टो का मेमोरी लॉस हो गया है।

आनेवाले कल में जो जानेवाले हैं, उन्हें चलाचली की बेला में भविष्य याद आ रहा है।

जनता ने जिनका बोरिया बिस्तर बाँध दिया है वो कोरे काग़ज़ को नक़्शे के रूप में पेश कर कल की योजना बनाने का नाटक न करें।

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2024-2026 कुल पृष्ठ : 48 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

रोटी और संसद

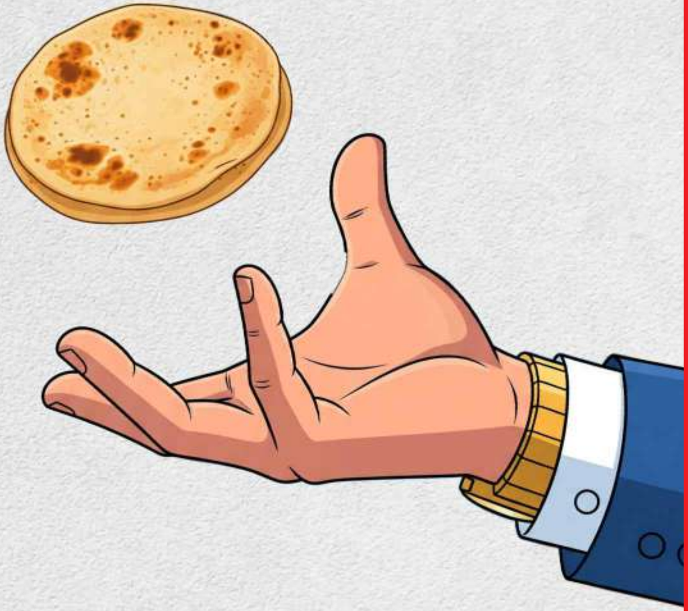

एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ--
'यह तीसरा आदमी कौन है ?'
मेरे देश की संसद मौन है।

- धूमिल

(साभार : कविता कोश)

समाजवादी पार्टी
/samajwadiparty
www.samajwadiparty.in
QR कोड स्कैन करें और वाट्स-एप चैनल से जुड़ें
/Akhilesh Yadav
/Samajwadi Party